

# भारत में न्यायिक व्यवस्था एवं मानवाधिकार की अवधारणा

चन्दन कुमार

अणुडाक— chandankumar621988@gmail.com

प्राप्त करता है, अतः व्यक्ति व राज्य के मध्य विरोधाभास का प्रज्ञ ही नहीं उठता, दोनों एक-दूसरे के पूरक है, परिणामतः दावों के रूप में

**संपूर्ण आलेखः(Full Paper)** — आज मानव अधिकारों का मुद्दा वैष्विक राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की न तो गुंजाइस है और न ही सरोकार का विषय है, सार्वभौमिकता की विषेषता जहाँ मानव अधिकारों के आवश्यकता है, प्लेटो का आदर्श राज्य न्याय की धारणा पर आधारित है, महत्व को रेखांकित करती है, वहीं यही विषेषता मानव अधिकारों की लेकिन प्लेटो न्याय का व्यापक अर्थ लेता है, न्याय का तात्पर्य है कि अवधारणा को विवादास्पद भी बना देती है, अधुनिक प्रजातांत्रिक समाजों प्रत्येक व्यक्ति अपने गुण का स्वभाव<sup>1</sup> अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन में व्यक्ति के कर्तपय मूलभूत अधिकारों को सर्वमान्य घोषित कर दिया है, करे तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करे प्लेटो की न्याय की धारणा परन्तु व्यवहार में इनका अनुपालन किसी समाज विषेष की आर्थिक, नागरिकों के कर्तव्यों पर बल देती है तथा यह व्यक्ति व राज्य (समाज) सांस्कृतिक व राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है तथा यह भी दोनों के विकास के लिए आवश्यक है, अरस्तू ने राज्य को एक प्राकृतिक सत्य है कि मानव अधिकारों की वर्तमान धारणा पच्चिमी देशों के व नैतिक संस्था माना है, व्यक्ति राज्य की गतिविधियों में भाग लिए बिना राजनीतिक व सामाजिक तथा आर्थिक मापदण्डों पर आधारित है, विवाद अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता, अतः राजनीतिक भागीदारी व्यक्ति की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पच्चिमी मापदण्डों पर आधारित इस के नैतिक विकास की पूर्व शर्त है यह उसका अधिकार नहीं है वरन् अवधारणा पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सार्वभौमिक रूप से लागू करने उसका दायित्व है कि अपने नैतिक विकास हेतु राज्य की गतिविधियों में का प्रयास किया जाता है, यद्यपि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्वतंत्र भागीदारी सुनिष्ठित करे राज्य साध्य है तथा व्यक्ति साधन है निष्कर्षतः राष्ट्रों पर बाध्यकारी सम्प्रभु शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी मानव अधिकारों प्रमुख यूनानी विचारकों ने राज्य व व्यक्ति को एक-दूसरे का पूरक मानते के अनुपालन की शर्त पच्चिमी देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का अंग बन हुए भी व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल दिया है।

गई है, अतः कोई भी राष्ट्र अब मानव अधिकारों के सरोकार से अछूता नहीं है, वैष्विकरण व उदारीकरण के वर्तमान युग में मानव अधिकारों का मुद्दा भी राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है इस परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों की अवधारणा का विलेषण आवश्यक प्रतीत होता है।

मध्ययुगीन यूरोप का इतिहास चर्च व सामन्तवादी राज्यों के मध्य प्रभुत्व हेतु संघर्ष का युग है, इस युग में यह मान्यता प्रबल थी कि व्यक्ति अपने धार्मिक जीवन में चर्च के अधीन है तथा राजनीतिक जीवन में राज्य के अधीन है, सेण्ट आगस्टाइन जैसे चिन्तकों ने राज्य के उपर चर्च की प्रभुता का समर्थन भी किया है, पोप गेलासियस ने दोनों की व्यक्ति के धार्मिक व राजनीतिक जीवन में अलग-अलग सत्ता स्वीकार की है इसे वर्तमान स्वरूप एक लम्बे विकास का दीर्घ मानवीय संघर्ष का परिणाम है, के संघर्ष में व्यक्ति के अधिकारों का कोई महत्व नहीं था, व्यक्ति राज्य अथवा चर्च दोनों में से किसी के विरुद्ध अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता था।

सम्बन्धों को परिभाषित करती है, प्राचीन भारतीय विचारकों ने धर्म के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति तथा व्यक्ति राज्य सम्बन्धों का विलेषण किया है, यहाँ धर्म का अर्थ पूजा-पाठ की किसी विषेष पद्धति से नहीं वरन् कर्तव्य व नैतिकता से है, महाभारत मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शासक व शासितों को धर्म कर्तव्य से इस प्रकार बांधने की कोषिष की गई है कि व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति स्वतः हो जाएगी, प्राचीन भारतीय विचारकों ने आज की पच्चिमी विचारधारा की भांति अधिकार की व्याख्या राज्य के विरुद्ध एक दावे के रूप में स्वीकार नहीं की, इसके विपरीत उन्होंने इस धारणा को स्वीकार किया है कि यदि समाज का प्रत्येक अंग अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, तो प्रत्येक के अधिकारों की पूर्ति स्वतः हो जाएगी, क्योंकि अधिकार व कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है।

प्रत्येक प्रकार के अधिकारों विषेषकर मानव अधिकारों की आधारिषिला इस धारणा पर आधारित है कि मानव गरिमायुक्त तथा विवेकषील प्राणी है तथा समाज की राज्य सहित सभी संस्थाओं का मूल उद्देश्य व्यक्ति का हित अथवा मानव कल्याण है वस्तुतः दावों के रूप में अधिकारों की धारणा की दार्शनिक आधारिषिला सर्वप्रथम पुनर्जागरण की क्रान्ति द्वारा रखी गई थी 15वीं शताब्दी में यूरोप ने पुनर्जागरण के इस विचार को अपना केन्द्र बिन्दु बनाया कि व्यक्ति एक गरिमायुक्त व विवेकषील प्राणी है तथा राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, पुनर्जागरण के इस मूल मंत्र की अभिव्यक्ति साहित्य कला, संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में हुई पुनर्जागरण ने जहाँ एक ओर व्यक्ति के उपर सामन्तवादी व चर्च के नियंत्रण व शोषण का अन्त किया, वही मानव केन्द्रित राजनीतिक व्यवस्थाओं के विकसित होने का मार्ग प्रस्तृत किया, वास्तव में प्रजातंत्र

प्राचीन यूनानी विचारकों ने भी राज्य व व्यक्ति के मध्य सम्बन्धों का दर्शनिक आधार पुनर्जागरण में ही निहित है।

आधुनिक युग के आरम्भ में ही यूरोप के राजनीतिक विचारकों ने एक तरफ जहाँ दैवीय राज्य की धारणा को नकार दिया, वहीं दूसरी ओर मानवनिर्मित तथा जनसहमति पर आधारित प्रजातांत्रिक राज्यों के विकास

का मार्ग प्रसरत किया तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं ने भी इसी दिशा में अधिकारों के महत्व को रेखांकित किया इस प्रकार द्वितीय विष्वयुद्ध के अपना योगदान दिया, यद्यपि 1215 के मैग्नाकार्टा महान अधिकार पत्र पूर्व ही व्यक्ति के नागरिक, सामाजिक व राजनीति अधिकारों को द्वारा जनता ने राजासेयह अधिकार प्राप्त कर लिया था कि राजा द्वारा आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का अंग मान लिया गया था।

नए कर लगानेसे पूर्व समाज के विभिन्न वर्गों से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन राजा की निरंकुषला पर प्रतिबंध तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारासता के स्थानान्तरण का कार्य 1688 की इंग्लैण्ड की गौरवपूर्ण क्रांति द्वारा कियागया, इस क्रांति ने इंग्लैण्ड में जनता के अधिकारों पर आधारित प्रजातांत्रिक शासन के विकास का रास्ता सृदृढ़ किया।

समझौतावादी राजनीतिक विचारकों हॉब्स, ब्लॉक व रसों ने राज्य को व्यक्तियों के आपसी समझौते का परिणाम बताया तथा व्यक्ति के निरंकुष, तानाषाही तथा प्रजातंत्र विरोधी राजनीतिक प्रवृत्तियों को बल प्राकृतिक अधिकारों को मान्य प्रदान की प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार है, मिला जिसके परिणामस्वरूप जर्मनी, इटली तथा जापान में प्रतिक्रिया स्वरूप अब यह प्रज्ञ विचारणीय है कि जब 20वीं शताब्दी के आरम्भ में व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों को मान्यता प्राप्त हो गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को मानव अधिकारों की अलग घोषणा क्यों करनी पड़ी? वास्तव में प्रथम विष्वयुद्ध ने ही यह सिद्ध कर दिया था कि राष्ट्रीय परिदृश्य अप्रभावित नहीं रह सकता प्रथम युद्ध के पश्चात व उसके परिणामस्वरूप जर्मनी, इटली तथा जापान में प्रतिक्रिया स्वरूप विष्वेषण कर विद्वानों ने इसके तमाम कारणों पर पकाष उला, यह माना प्राकृतिक अधिकारों की धारणा व्यक्ति के समस्त अधिकारों सहित मानव गया कि इस युद्ध का एक प्रमुख कारण जापान जर्मनी तथा अठली जैसे अधिकारों कामूल श्रोत है, ब्रिटिष विचारक जॉन लॉक ने इंग्लैण्ड की देशों में प्रजातंत्र व नागरिक अधिकारों का अभाव है जिससे शासकों ने गौरवपूर्ण क्रान्ति की उपलब्धियों का समर्थन किया तथा उदारवादी निरंकुष नीतियों को अपनाया ताकि विष्व को युद्ध की विभीषिका में झोंक विचारधारा पर आधारित सीमित प्रजातांत्रिक शासन का सूत्रपात गया कि इस युद्ध का एक प्रमुख कारण जापान जर्मनी तथा अठली जैसे लॉक का सबसे महत्वपूर्ण विचार प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है उसने चार स्वतंत्रताओं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उपासना की स्वतंत्रता भय से जीवन, स्वतंत्रता ताकि सम्पत्ति के तीन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों स्वतंत्रता तथा अभाव से स्वतंत्रता को अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा की की श्रेणी में रखा, जो व्यक्ति को राज्य की उत्पत्ति से पूर्व जन्म से ही आवश्यक शर्त बताया, यद्यपि विभिन्न नागरिक अधिकारों की व्यवस्था प्राप्त है, बल्कि राज्य का निर्माण इन प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के संविधान व कानूनों में की जाती है तथा देश ही किया जाता है, यदि राजनीतिक समाज इन अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका द्वारा उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है, परन्तु में असफल होता है या वह स्वयं इन अधिकारों का उल्लंघन करता है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों की कोई धारणा प्रचलित नहीं थी, जो कि तो व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वे क्रांति द्वारा सरकार को बदल दें, द्वितीय विष्वयुद्ध के उपरांत अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के लिए आवश्यक प्राकृतिक अधिकारों की उक्त धारणा ने समस्त आधुनिक जनक्रान्तियों की पूर्ति के लिए की गई अतः तथा मानव अधिकारों की वर्तमान अवधारणा को प्रेरित किया है।

अधिकारों की धारणा को दृढ़ता प्रदान करने तथा व्यक्तियों के कठिपय अधिकारों को जन्मजात अधिकारों के रूप में सर्वमान्य बनाने में अमरीका व फ्रांस की क्रान्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है, अमरीकी क्रांति 1776 की घोषणा में कहा गया, हम इस सत्य को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि मनुष्यों को समान बनाया गया है, अर्थात् समानता का अधिकार एक स्वयंसिद्ध

अधिकार है, इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने स्वतंत्रता समानता तथा मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो बन्धुत्व के तीन नारों का उद्घोष किया, जो वर्तमान मानवीय अधिकारों सभी व्यक्तियों व उनके समूहों को मानव होने के परिणामस्वरूप प्राप्त है, के आधार बन गए है, क्रांसीसी क्रांति के उपरांत जारी अधिकारों के अर्थात् मानव अधिकार जीवन की वे परिस्थितियों हैं जो मानव प्राणी के घोषणा पत्र में कहा गया कि व्यक्ति अपने अधिकारों के संबंध में स्वतंत्र रूप में सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव जैसे जाति, धर्म, जन्म व समान पैदा हुए हैं अर्थात् स्वतंत्रता व समानता के अधिकारों को स्थान लिंग आदि के प्राप्त हैं, मानव अधिकारों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्मजात अधिकार माना गया अधिकारों की इस उदीयमान विषेषता उनकी सार्वभौमिकता है अर्थात् ये अधिकार बिना किसी भेदभाव धारणा ने उदारवादी प्रजातंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है के सभी मानव प्राणियों को उपलब्ध होने चाहिए, दूसरी विषेषता यह है लेकिन उदारवादी अधिकारों की उक्त धारणा केवल राजनीतिक व कि ये अधिकार व्यक्ति के रूप में विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ हैं अर्थात् इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व व क्षमताओं का विकास नहीं हो सकता, तीसरी विषेषता यह है कि ये अधिकार स्वयंसिद्ध सत्य है तथा

व्यक्ति को जन्म से प्राप्त है, अतः चूँकि मानव अधिकारों को राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्रदान नहीं किया गया इसलिए राज्य द्वारा इन्हें छीना नहीं जा सकता है, इस विषेषता को मानव अधिकारों की अदेयता भी कहते हैं, मानव अधिकारों की चौथी विभिन्न प्रकार के मानव अधिकारों को अधिभाज्य तथा अन्तः सम्बन्धित माना गया है, अर्थात् मानव अधिकारों की श्रेणी में जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार हैं, वे आपस में एक-दूसरे के पूरक हैं तथा उन्हें लागू करने में पारस्परिक भेदभाव या विभाजन नहीं किया जा सकता।

जैसा कि उपर बताया गया है कि द्वितीय विष्व युद्ध के उपरान्त व्यक्ति सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, प्राचीन स्ट्रोइक विचारकों ने के अधिकार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का सरोकार बन गए तथा उनका नए यह प्रतिपादन किया था कि मानव व्यवहार का मूल्यांकन प्राकृतिक सिरे से संहिताकरण कर मानव अधिकारों की संज्ञा दी गई, सर्वप्रथम नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए, इसके बाद रोमन विचारकों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने मौलिक मानव अधिकारों तथा व्यक्ति की गरिमा में जसजेष्टियम का विस्तार दिया जिसके अनुसार राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर आस्था व्यक्ति की तत्पञ्चात् संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 व्यक्तियों के कुछ सार्वजनिक अधिकार हैं प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया, इसीलिए का व्यापक विलेषण व समर्थन समझौतावादी विचारकों हॉब्स, लॉक व प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता रुसों द्वारा किया गया था इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों को जन्म से है इस घोषणा में सभी व्यक्तियों के कातिपय सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक अवस्था में (राज्य निर्माण से पूर्व की अवस्था) कातिपय अधिकार आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया, सार्वभौमिक प्राप्त हैं जिन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है चूँकि ये अधिकार व्यक्ति घोषणा के अनुच्छेद एक में कहा गया, सभी व्यक्ति सम्मान व अधिकारों को जन्म से प्राप्त है, तथा राज्य द्वारा नहीं प्रदान किए गए हैं, अतः राज्य की दृष्टि से समान पैदा हुए हैं सभी व्यक्ति विवेक व चेतना से युक्त है, द्वारा इन्हें वापस अथवा नियंत्रित नहीं किया जा सकता मानव अधिकारों इसी घोषणा के अनुच्छेद दो में विष्वास व्यक्ति किया गया कि सभी को स्वयंसिद्ध सत्य मानना ताकि उनकी अदेयता व सार्वभौमिकता इसी व्यक्ति इस घोषणा में उल्लिखित सभी स्वतंत्रताओं को बिना किसी प्रकार सिद्धांत से प्रेरित है।

के भेदभाव के प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके उपरान्त संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के सम्बन्ध में दो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को स्वीकार किया है, प्रथम 1966 में पारित नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय संघि तथा द्वितीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, इन दोनों सम्बन्धों को अधिकांश राष्ट्रों ने मान्यता प्रदान कर दी है, ये दोनों सम्बन्धों इस मान्यता के परिणामस्वरूप 1976 से प्रभावी हो गई, इन दो सम्बन्धों सहित मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को मानव अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय संहिता के रूप में जाना जाता है, इस संहिता के अनुसार पाँच प्रकार के मानव अधिकार हैं, प्रथम, नागरिक अधिकार, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार दास परिस्थितियों का समाप्ति, न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का अधिकार शामिल है, दूसरे, विकास सम्भव नहीं है, इसीलिए ये अधिकार सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार, जिनमें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का रूप से प्राप्त होने चाहिए, मानव अधिकारों की व्याख्या करने वाला चौथा अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, शरण पाने का अधिकार आदि सम्मिलित है, तीसरे आर्थिक अधिकार, जिनमें सम्पत्ति का अधिकार सम्मान इसलिए करते हैं कि इससे उनके अधिकार सुरक्षित होते हैं यह विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, समान कार्य के अधिकारों का संरक्षण उनके हित में है भारतीय विद्वान नीरज नाथवानी ने लिए समान वेतन का अधिकार, जीविका निर्वाहन हेतु पर्याप्त साधन पाने का अधिकार आदि शामिल है, चौथे, सामाजिक अधिकार, जिनमें विवाह करने व परिवार स्थापित करने का अधिकार, परिवार के संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार आदि सम्मिलित हैं पांचवें, सांस्कृतिक अधिकार जिनमें समुदाय के संस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार, सांस्कृतिक कृतियों के संरक्षण का अधिकार आदि सम्मिलित है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समय-समय पर विषिष्ट वर्गों के हितों की रक्षा हेतु अन्य विषिष्ट मानवाधिकारों को भी मान्यता प्रदान की है तथा मानवाधिकारों का विस्तार किया है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध 1969 में महासभा ने सभी प्रकार के जातीय भेदभाव को समाप्त करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय को स्वीकृति प्रदान की थी इसी प्रकार महासभा ने 1979 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने का अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय स्वीकार किया बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु वर्ष 1989 में महासभा ने एक अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय स्वीकार किया है, अतः वर्तमान में मानवाधिकारों के दायरे में केवल सामान्य मानवाधिकार ही समिलित नहीं है, वरन् विषिष्ट वर्गों के अधिकारों को भी मान्यता प्रदान कर दी गई है।

मानवाधिकारों के अस्तित्व को उचित ठहराने हेतु समय-समय पर विभिन्न सिद्धान्तों का सहारा लिया गया है इस सम्बन्ध में सबसे प्रचलित

मानव अधिकारों का दूसरा सिद्धांत पारस्परिकता का नैतिक नियम है, इस नियम के अनुसार, हमे दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम दूसरों से अपने प्रति व्यवहार करना चाहते हैं, इस नियम का यह सुनिष्चित करता है कि हमारे अधिकारों का संरक्षण स्वतः सुनिष्चित होगा, यह नियम मूल रूप से विष्व के प्रमुख धर्मों में पाया जाता है, विष्व धर्मों की संसद ने अपने 1993 में जारी वैष्विक नैनिकता के नियमों में इसे स्थान प्रदान किया है।

मानवाधिकारों के विषय में तीसरा सिद्धांत जॉन फिनिस द्वारा प्रतिपादित साधन सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार मानव अधिकार वह परिस्थितियों का सान है, जिसके बिना व्यक्ति का मानव के रूप में प्रथा की समाप्ति, न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया का अधिकार शामिल है, दूसरे, विकास सम्भव नहीं है, इसीलिए ये अधिकार सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार, जिनमें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का रूप से प्राप्त होने चाहिए, मानव अधिकारों की व्याख्या करने वाला चौथा अधिकार, राष्ट्रीयता का अधिकार, शरण पाने का अधिकार आदि सिद्धांत हित सिद्धांत है, जिसके अनुसार व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का सम्मिलित है, तीसरे आर्थिक अधिकार, जिनमें सम्पत्ति का अधिकार सम्मान इसलिए करते हैं कि इससे उनके अधिकार सुरक्षित होते हैं यह विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, समान कार्य के अधिकारों का संरक्षण उनके हित में है भारतीय विद्वान नीरज नाथवानी ने लिए समान वेतन का अधिकार, जीविका निर्वाहन हेतु पर्याप्त साधन पाने का अधिकार आदि शामिल है, चौथे, सामाजिक अधिकार, जिनमें विवाह करने व परिवार स्थापित करने का अधिकार, परिवार के संरक्षण का अधिकार, विकास का अधिकार आदि सम्मिलित हैं पांचवें, सांस्कृतिक अधिकार जिनमें समुदाय के संस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार, सांस्कृतिक कृतियों के संरक्षण का अधिकार आदि सम्मिलित है।

यद्यपि मानव अधिकारों को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता प्राप्त हो चुकी है तथा मानव अधिकार राष्ट्रों की प्रगति का मापदण्ड भी बनचुके आज के पारस्परिक निर्भरता वाले युग में मानव केन्द्रित सुरक्षा का वृष्टिकोण व्यक्ति व समाज दोनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक है, इस सिद्धांत के अनुसार मानव अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था वैष्विक स्तर पर मानव सुरक्षा हेतु आवश्यकता है।

संस्कृति द्वारा विकसित नहीं किए गए, इसी आधार पर एडमण्ड बर्क ने फ्रांसीसी समाज में स्वाभाविक ढंग से नहीं हुआ था, यदि हम मानव अधिकारों को समाज तथा संस्कृति से विकसित मान तेले हैं तो मानव अधिकारों की कोई सार्वभौमिक धारणा नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक देष की संस्कृति की समाज में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसी आधार पर 1990 में सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन यी तथा मलेशिया के नेता महथिर मोहम्मद ने तर्क दिया था कि एथिया में सामाजिक मूल्य पञ्चिमी देषों से इस अर्थ में भिन्न है कि यहाँ वैयक्तिक स्वतंत्रता के स्थान पर संदर्भ ग्रंथ सूची

सामाजिक स्थायित्व व सम्पन्नता को अधिक महत्व दिया गया है तथा मानव अधिकारों की वर्तमान धारणा एथियाई देषों पर बाहर से थोपी हुई प्रतीत होती है।

मानव अधिकारों की एक अन्य आलोचना कानूनी दार्शनिकों जैसे बेन्थम आदि ने की है उनके अनुसार राज्य के विरुद्ध उसकी मान्य के बिना

कोई प्राकृतिक अथवा मानव अधिकार नहीं हो सकते, उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को Non- Sense Upon Stills कहकर उनकी निन्दा की नई दिल्ली।

है ऐतिहासिकतावादी विचारक जैसे सर हेनरी मेन तथा सैविंग्सनी ने माना

है कि वही अधिकार मान्य है, जिनका ऐतिहासिक दृष्टि से किसी समाज में विकास हुआ है, अधिकार बाहर से थोपे नहीं जा सकते, 20वीं शताब्दी इलाहाबाद।

के तार्किक प्रत्यक्ष वादियों ने मानव अधिकारों को केवल नैतिक घोषनाएं

माना है जो मान्य नहीं है, क्योंकि अनुभव के आधार पर उनका सत्यापन नहीं किया जा सकता है, यद्यपि कार्ल मार्क्स के विचारों से मनुष्य के

आर्थिक व सामाजिक अधिकारों को प्रेरणा मिली है, परन्तु उसने स्वयं व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा को महत्व न देकर आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों को अपने विचारों में अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है।

मानव अधिकारों की दूसरी श्रेणी में वे आलोचक आते हैं जिसके अंतर्गत आलोचकों ने मानव अधिकारों की अविभाज्यता व सार्वभाविकता की

विषेषताओं को स्वीकार नहीं किया है औलिविया बाल तथा पॉल ग्रीडी जैसे आलोचकों ने मानव अधिकारों की अविभाज्यता को स्वीकार नहीं किया है उनके अनुसार राजनीतिक व नागरिक अधिकार अन्य अधिकारों

जैसे सामाजिक व आर्थिक अधिकारों से इस अर्थ में भिन्न है कि सामाजिक व आर्थिक अधिकार अनिव्यत प्रकृतिक के हैं, इनको लागू करने हेतु धन की आवश्यकता होती है तथा इनकी प्रकृति सकारात्मक है,

जबकि ये विषेषताएं नागरिक व राजनीतिक अधिकारों में नहीं पाई जाती हैं, फिलिप एल्स्टन ने भी माना है कि सभी अधिकार एक जैसे नहीं हैं उन्हें लागू करने में आपसी प्रमुखता प्रदान किया जाना आवश्यक है इसी

प्रकार सांस्कृतिक सापेक्षतावाद व विषिष्टता के अधिकार पर आलोचक मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता को स्वीकार नहीं करते हैं।

उक्त आलोचनाओं का व्यावहारिक पहलू है कि तीसरी दुनिया के अधिकांश देष मानव अधिकारों को यूरोप की ईसाई परम्परा से प्रेरित मानते हैं तथा अपनी विषिष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक परम्पराओं के आधार पर उनका थोपा जाना स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि अधिकांश यूरोपीय देष मानव अधिकारों के अनुपालन में अपने को अग्रणी मानते हुए अन्य देषों से उन्हें इसी रूप में लागू किया जाना आवश्यक समझते हैं, यह विवाद अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में कई बार उभर कर आ चुका है, संक्षेप में मानव अधिकारों की अवधारणा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा सामान्य रूप से अनुमान होते हुए भी अनुपालन के स्तर पर जटिल विवादास्पद है।

1. वेब दुनिया— जानिए क्या है समान नागरिक संहिता।

2. जागरण जोष, (स्पेषल), 26 दिसम्बर 2019 — समान नागरिक संहिता भारत के लिए क्यों जरुरी है।

3. वसु, दूर्गादास— भारत का संविधान, एक परिचय, लेकिसस—नेविसस, अधिकारों को Non- Sense Upon Stills कहकर उनकी निन्दा की नई दिल्ली।

4. उपाध्याय जय-जय राम, भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, में विकास हुआ है, अधिकार बाहर से थोपे नहीं जा सकते, 20वीं शताब्दी इलाहाबाद।

5. पाण्डेय, जय नारायण— भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, नहीं किया जा सकता है, यद्यपि कार्ल मार्क्स के विचारों से मनुष्य के इलाहाबाद।

6. प्रतियोगिता दर्पण — 2010

7. कुरुक्षेत्र— 2001

8. प्रतियोगिता दर्पण— 2011